



Neutral Citation No. - 2026:AHC:166695

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या - 3168 वर्ष 2026

एक्स किशोर

..... पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

..... विपक्षी पक्षकार(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) की ओर से अधिवक्ता : देवेन्द्र सिंह

विपक्षी पक्षकार(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चन्द्र शर्मा

विपक्षी पक्षकार पर नोटिस की तामील हो जाने के बावजूद, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को छोड़कर उसकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने वास्तविक मामा के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा 102 के अंतर्गत (जिसे आगे "किशोर न्याय अधिनियम, 2015" कहा गया है) वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार करने तथा विद्वान विशेष न्यायाधीश/किशोर न्यायालय/अपर सत्र न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अधिनियम), फतेहपुर द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 04/2026 में पारित दिनांक 13.03.2026 के निर्णय एवं आदेश तथा किशोर न्याय बोर्ड, फतेहपुर द्वारा पारित दिनांक 05.02.2026 के आदेश को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, पुनरीक्षणकर्ता को थाना हथगांव, जनपद फतेहपुर में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 110, 351(3), 352, 115(2), 191(3), 191(2), 103(1) के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 193/2025 में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की आयु लगभग 16 वर्ष थी और वह कृत्य की प्रकृति को समझने की स्थिति में नहीं था। आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मारपीट करने के लिए 9 अभियुक्तों के नाम दिए गए थे, जिसमें चोटों के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वर्तमान पुनरीक्षणकर्ता/किशोर को सामान्य भूमिका के अतिरिक्त कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई थी। आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि शेष अभियुक्त वयस्क हैं और इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा उन्हें पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। वर्तमान पुनरीक्षणकर्ता का मामला अलग आधार पर नहीं रखा जा सकता है।

यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया गया और यहां तक कि परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी विचार नहीं किया गया। अपीलीय न्यायालय ने भी इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया, बल्कि अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना तथा उक्त अधिनियम की धारा 12 में निहित विधि पर विचार किए बिना जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के अन्य अपराधियों की संगति में सम्मिलित होने की संभावना की आशंका का उल्लेख विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश में किया गया है और अपीलीय न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, जबकि अभिलेख पर उपलब्ध परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में ऐसी कोई संभावना व्यक्त नहीं की गई है। विधि का उल्लंघन करने वाला बालक दिनांक 06.11.2025 से किशोर देखरेख गृह में है और उसका मनोविज्ञान

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। अतः किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने तथा दाण्डिक पुनरीक्षण को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपर्युक्त प्रार्थना का विरोध किया।

वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क, अभिलेख के परिशीलन, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों, परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु, पुनरीक्षणकर्ताओं की आयु तथा इस तथ्य पर कि समान भूमिका वाले अन्य सह-अभियुक्तों को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है और विधि का उल्लंघन करने वाले बालक/आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है, विचार करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर समुचित रूप से विचार नहीं किया, बल्कि अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार, इस पुनरीक्षण में आधार प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं।

तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 05.02.2026 को तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.03.2026 को पारित आदेशों को एतद्वारा **अपास्त** किया जाता है और वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण एतद्वारा **स्वीकार** किया जाता है।

यह निर्देशित किया जाता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक/आवेदक को पुनरीक्षणकर्ता (विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के वास्तविक मामा) द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करने पर, संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(i) पुनरीक्षणकर्ता/वास्तविक मामा यह वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि जमानत पर रिहा होने के पश्चात् पुनरीक्षणकर्ता को किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी अथवा उसे किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा और आगे यह कि वास्तविक मामा यह सुनिश्चित करेगा कि किशोर द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति न की जाए।

(ii) पुनरीक्षणकर्ता/वास्तविक मामा आगे इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि किशोर अपनी उपयुक्त स्तर की शिक्षा जारी रखेगा, जिसके लिए उसे अन्य रचनात्मक गतिविधियों के साथ-साथ प्रोत्साहित किया जाएगा और उसे अनुत्पादक तथा अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) किशोर तथा पुनरीक्षणकर्ता/वास्तविक मामा प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे।

(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा और नियमित रूप से उसकी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को ऐसी आवधिक अवधि के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि किशोर न्याय बोर्ड निर्धारित करे।

10 अगस्त, 2026

अशोक गुप्ता

(न्यायमूर्ति सुभाष चन्द्र शर्मा)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”